



नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 351
दि. 24.04.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। ऐसे में हम निश्चित रूप से 27 में वही चेहरा होंगे।' - नितिन नवीन

(जीएनएस)।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगमीं शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी के दायरी से 'मिशन-2027' का आगाज किया, तो बीजेपी ने भी अपना प्लान साफ कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि 2027 के चुनाव में पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे।

सबसे स्पष्ट संकेत हैं कि योगी के नाम पर चुनाव लड़कर सत्ता की हैट्टिक लगाने का लक्ष्य।
नितिन नवीन ने इंटरव्यू में यूपी की बदलती तस्वीर को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि पहले यूपी को 'वसूली और अपराध' के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह 'बेहतर कानून व्यवस्था और एक्सप्रेसवे' के लिए चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की जोड़ी को श्रेय देते हुए उन्होंने यूपी को 'उत्तम प्रदेश' बनाने की प्रक्रिया का जिक्र किया।

नवीन ने जोर दिया कि अच्छा शासन (गुड गवर्नेंस), विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और गरीब कल्याण योजनाओं का जमीन तक पहुंचना, ये सब आम जनता को वोट देने का कारण बनते हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की 'लॉ एंड ऑर्डर' को यूपी की सबसे बड़ी

वजह बताया और कहा कि आज कई शहर विकसित नजर आ रहे हैं। 'ये सब चीजें हमारे लिए तीसरी सरकार बनाने और हैट्टिक लगाने के लिए काफी हैं', नितिन नवीन का यह वाक्य बीजेपी की आत्मविश्वास से भरी रणनीति को दिखाता है।

2017 में जब बीजेपी 15 साल बाद सत्ता में लौटी थी, तब पार्टी ने किसी नेता को सीएम फेस घोषित नहीं किया था। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीएम मोदी के नाम और काम पर चुनाव लड़ा गया। प्रचंड बहुमत के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक़्त योगी ने हिंदुत्व के साथ-साथ कानून व्यवस्था की मजबूत बुनियाद रखी। 2022 के चुनाव में बीजेपी की सीटें थोड़ी कम हुईं, लेकिन बहुमत बना रहा। उस समय चुनाव से पहले सीएम

स्पष्टता और उत्साह। विपक्ष को पहले से ही मुकाबले का अंदाजा।
यूपी का बदलाव: बीजेपी क्या दावे

कर रही है? अपराध और वसूली से मुक्ति, मजबूत लॉ एंड ऑर्डर। तेज विकास। गरीब कल्याण योजनाओं (जैसे पीएम अन्न योजना) का नीचे तक पहुंच। बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना। जाति के आधार पर भ्रम फैलाने की राजनीति की जगह विकास की राजनीति।

बीजेपी का मानना है कि आम आदमी इन ठोस कामों को देखकर वोट देता है। योगी की सरकार ने यूपी को 'बिमारू' राज्य की छवि से निकालकर विकास के नए आयाम दिए हैं, यही पार्टी का मुख्य चुनावी नैरेटिव है।

सियासी मायने: हैट्टिक की राह कितनी आसान? नितिन नवीन का बयान कई संकेत देता है: पार्टी में एकजुटता: राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर योगी को समर्थन देकर बीजेपी ने अंदरूनी कलह की किसी भी अफवाह पर धरम लगा दिया।
विपक्ष पर दबाव: सपा-कांग्रेस गठबंधन अभी से मिशन-2027 की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी ने पहले ही अपना चेहरा क्लियर कर दिया।
उत्तराखंड का मैसेज: धामी को भी चेहरा बताकर बीजेपी ने हिमालयी राज्य में भी स्थिरता का संदेश दिया।

एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में नितिन नवीन ने कहा, 'योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। ऐसे में हम निश्चित रूप से वही चेहरा होंगे।' उत्तराखंड (व३३१११११) के बारे में पूछे जाने पर भी उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पार्टी का चेहरा बताया। यह बयान बीजेपी की तरफ से 2027 के लिए

कोलकाता से दूर हैं। 2021 के चुनाव में 152 सीटों में से वोट उने 92 और इच्छ में 59 सीटें जीती थीं।
इस बार 91% का आंकड़ा छूना एक अलग ही कहानी बना कर रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जब मतदान प्रतिशत में इतना बड़ा उछाल आता है, तो वह किसी न किसी 'लहर' का संकेत होता है। इस बार

देश का पहला चुनाव, बंगाल में सिर्फ 42.23% वोटिंग हुई थी। 1977: वामपंथ (छा३३ ऋड्वल्ल३) के उदय के समय यह आंकड़ा 70% के पार चला गया। 2006: बुद्धदेव भट्टाचार्य के दौर में वोटिंग 81% तक पहुंची। 2011 (ऐतिहासिक बदलाव): जब ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी किले को ढहाया, तब रिकॉर्ड 84.33% मतदान हुआ था।
यह पैटर्न बताता है कि जब भी बंगाल में सत्ता परिवर्तन की सुगबुहाट होती है, वोटिंग का ग्राफ तेजी से ऊपर भागता है। 2011 का उदाहरण सबसे सटीक है, जहां बंपर वोटिंग ने वामपंथ की विदाई तय कर दी थी। क्या 2026 में भी इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है?

यह पैटर्न बताता है कि जब भी बंगाल में सत्ता परिवर्तन की सुगबुहाट होती है, वोटिंग का ग्राफ तेजी से ऊपर भागता है। 2011 का उदाहरण सबसे सटीक है, जहां बंपर वोटिंग ने वामपंथ की विदाई तय कर दी थी। क्या 2026 में भी इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है?

2011 का उदाहरण क्यों बार-बार दिया जा रहा है? 2011 का चुनाव बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। उस समय राज्य में लगभग 84 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुआ था। उसी चुनाव में 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार सत्ता से बाहर हुई और ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई।
इसी वजह से जब भी बंगाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, राजनीतिक विश्लेषक 2011 के चुनाव की तुलना शुरू कर देते हैं। हालांकि हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। 2025 में भी विपक्ष दावा कर रहा है कि ज्यादा वोटिंग बदलाव का संकेत है, जबकि वोट उने अपने समर्थन का प्रमाण बता रही है।

उत्कृष्ट परिणाम आने पर विद्यालय

मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया। स्कूल प्रबंधन ने भी दोनों मेधावी छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। वहीं प्रतापगढ़ के सत्यम यादव ने 583 अंक पाकर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। उनके 97.17 प्रतिशत अंक बन रहे हैं। सत्यम यादव के पिता समर यादव ईंट

2027 की चुनौती: यूपी में 403 सीटों का विशाल मैदान। पिछले दो चुनावों में मिले बहुमत को बरकरार रखना और बढ़ाना बीजेपी के लिए बड़ी परीक्षा होगी। विपक्ष इस बयान को 'अति आत्मविश्वास' बता सकता है, लेकिन बीजेपी इसे 'जनता के बीच किए गए काम का नतीजा' मान रही है।
नितिन नवीन के बयान के बाद अब बीजेपी का फोकस बृहत् स्तर पर संगठन मजबूत करने, विकास कार्यों को और तेज करने और विपक्ष की 'जाति-धर्म' की राजनीति का मुकाबला 'विकास और सुशासन' से करने पर होगा।

बंगाल में 91% रिकॉर्ड मतदान टीएमसी या भाजपा किसके पक्ष में? रहस्य ईवीएम में बंद, 4 मई को खुलेगा

(जीएनएस)।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पहला चरण खत्म हो चुका है, लेकिन असली चर्चा अब वोटिंग प्रतिशत को लेकर हो रही है। पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। 16 जिलों की 152 सीटों पर हुए इस मतदान में चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक ही 91.35 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई है। यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि बंगाल के चुनावी इतिहास के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करने की दिशा में बढ़ रहा है।

पश्चिम बंगाल लंबे समय से हाई वोटिंग प्रतिशत वाले राज्यों में शामिल रहा है। यहां चुनावों में लोगों की भागीदारी आमतौर पर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा रहती है। लेकिन जब मतदान 90 प्रतिशत के आसपास पहुंच जाए, तो उसका राजनीतिक असर अलग तरीके से देखा जाता है।

कोलकाता से दूर हैं। 2021 के चुनाव में 152 सीटों में से वोट उने 92 और इच्छ में 59 सीटें जीती थीं।
इस बार 91% का आंकड़ा छूना एक अलग ही कहानी बना कर रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जब मतदान प्रतिशत में इतना बड़ा उछाल आता है, तो वह किसी न किसी 'लहर' का संकेत होता है। इस बार

देश का पहला चुनाव, बंगाल में सिर्फ 42.23% वोटिंग हुई थी। 1977: वामपंथ (छा३३ ऋड्वल्ल३) के उदय के समय यह आंकड़ा 70% के पार चला गया। 2006: बुद्धदेव भट्टाचार्य के दौर में वोटिंग 81% तक पहुंची। 2011 (ऐतिहासिक बदलाव): जब ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी किले को ढहाया, तब रिकॉर्ड 84.33% मतदान हुआ था।
यह पैटर्न बताता है कि जब भी बंगाल में सत्ता परिवर्तन की सुगबुहाट होती है, वोटिंग का ग्राफ तेजी से ऊपर भागता है। 2011 का उदाहरण सबसे सटीक है, जहां बंपर वोटिंग ने वामपंथ की विदाई तय कर दी थी। क्या 2026 में भी इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है?

इसी वजह से जब भी बंगाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, राजनीतिक विश्लेषक 2011 के चुनाव की तुलना शुरू कर देते हैं। हालांकि हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। 2025 में भी विपक्ष दावा कर रहा है कि ज्यादा वोटिंग बदलाव का संकेत है, जबकि वोट उने अपने समर्थन का प्रमाण बता रही है।

उत्कृष्ट परिणाम आने पर विद्यालय

मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया। स्कूल प्रबंधन ने भी दोनों मेधावी छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। वहीं प्रतापगढ़ के सत्यम यादव ने 583 अंक पाकर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। उनके 97.17 प्रतिशत अंक बन रहे हैं। सत्यम यादव के पिता समर यादव ईंट

2027 की चुनौती: यूपी में 403 सीटों का विशाल मैदान। पिछले दो चुनावों में मिले बहुमत को बरकरार रखना और बढ़ाना बीजेपी के लिए बड़ी परीक्षा होगी। विपक्ष इस बयान को 'अति आत्मविश्वास' बता सकता है, लेकिन बीजेपी इसे 'जनता के बीच किए गए काम का नतीजा' मान रही है।
नितिन नवीन के बयान के बाद अब बीजेपी का फोकस बृहत् स्तर पर संगठन मजबूत करने, विकास कार्यों को और तेज करने और विपक्ष की 'जाति-धर्म' की राजनीति का मुकाबला 'विकास और सुशासन' से करने पर होगा।

इस रिकॉर्ड वोटिंग ने राजनीतिक विश्लेषकों, दलों और चुनावी रणनीतिकारों को नया गणित सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह है कि क्या इतनी भारी वोटिंग सत्ता परिवर्तन का संकेत देती है या फिर इसका फायदा मौजूदा सरकार को मिलता है।
आखिर इस 'बंपर वोटिंग' का असली हकदार कौन है? क्या यह ममता बनर्जी के 'विकास' पर मुहर है या फिर परिवर्तन की वो आंधी, जिसका दावा बीजेपी लंबे समय से कर रही है?

पहले चरण में जिन 152 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां 2021 विधानसभा चुनाव में करीब 83.17 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं 2016 में यह आंकड़ा लगभग 82.66 प्रतिशत था।
आखिर इस 'बंपर वोटिंग' का असली हकदार कौन है? क्या यह ममता बनर्जी के 'विकास' पर मुहर है या फिर परिवर्तन की वो आंधी, जिसका दावा बीजेपी लंबे समय से कर रही है?

पश्चिम बंगाल लंबे समय से हाई वोटिंग प्रतिशत वाले राज्यों में शामिल रहा है। यहां चुनावों में लोगों की भागीदारी आमतौर पर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा रहती है। लेकिन जब मतदान 90 प्रतिशत के आसपास पहुंच जाए, तो उसका राजनीतिक असर अलग तरीके से देखा जाता है।

कोलकाता से दूर हैं। 2021 के चुनाव में 152 सीटों में से वोट उने 92 और इच्छ में 59 सीटें जीती थीं।
इस बार 91% का आंकड़ा छूना एक अलग ही कहानी बना कर रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जब मतदान प्रतिशत में इतना बड़ा उछाल आता है, तो वह किसी न किसी 'लहर' का संकेत होता है। इस बार

देश का पहला चुनाव, बंगाल में सिर्फ 42.23% वोटिंग हुई थी। 1977: वामपंथ (छा३३ ऋड्वल्ल३) के उदय के समय यह आंकड़ा 70% के पार चला गया। 2006: बुद्धदेव भट्टाचार्य के दौर में वोटिंग 81% तक पहुंची। 2011 (ऐतिहासिक बदलाव): जब ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी किले को ढहाया, तब रिकॉर्ड 84.33% मतदान हुआ था।
यह पैटर्न बताता है कि जब भी बंगाल में सत्ता परिवर्तन की सुगबुहाट होती है, वोटिंग का ग्राफ तेजी से ऊपर भागता है। 2011 का उदाहरण सबसे सटीक है, जहां बंपर वोटिंग ने वामपंथ की विदाई तय कर दी थी। क्या 2026 में भी इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है?

इसी वजह से जब भी बंगाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, राजनीतिक विश्लेषक 2011 के चुनाव की तुलना शुरू कर देते हैं। हालांकि हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। 2025 में भी विपक्ष दावा कर रहा है कि ज्यादा वोटिंग बदलाव का संकेत है, जबकि वोट उने अपने समर्थन का प्रमाण बता रही है।

उत्कृष्ट परिणाम आने पर विद्यालय

मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया। स्कूल प्रबंधन ने भी दोनों मेधावी छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। वहीं प्रतापगढ़ के सत्यम यादव ने 583 अंक पाकर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। उनके 97.17 प्रतिशत अंक बन रहे हैं। सत्यम यादव के पिता समर यादव ईंट

बंगाल जैसे राज्य में, जहां चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि भावनात्मक और वैचारिक संघर्ष भी होता है, वहां रिकॉर्ड वोटिंग का मतलब हमेशा सीधा नहीं होता। इस खास रिपोर्ट में हम समझाएंगे कि इस भारी मतदान के पीछे का असली खेल

पहले चरण में जिन 152 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां 2021 विधानसभा चुनाव में करीब 83.17 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं 2016 में यह आंकड़ा लगभग 82.66 प्रतिशत था।
आखिर इस 'बंपर वोटिंग' का असली हकदार कौन है? क्या यह ममता बनर्जी के 'विकास' पर मुहर है या फिर परिवर्तन की वो आंधी, जिसका दावा बीजेपी लंबे समय से कर रही है?

पश्चिम बंगाल लंबे समय से हाई वोटिंग प्रतिशत वाले राज्यों में शामिल रहा है। यहां चुनावों में लोगों की भागीदारी आमतौर पर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा रहती है। लेकिन जब मतदान 90 प्रतिशत के आसपास पहुंच जाए, तो उसका राजनीतिक असर अलग तरीके से देखा जाता है।

कोलकाता से दूर हैं। 2021 के चुनाव में 152 सीटों में से वोट उने 92 और इच्छ में 59 सीटें जीती थीं।
इस बार 91% का आंकड़ा छूना एक अलग ही कहानी बना कर रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जब मतदान प्रतिशत में इतना बड़ा उछाल आता है, तो वह किसी न किसी 'लहर' का संकेत होता है। इस बार

देश का पहला चुनाव, बंगाल में सिर्फ 42.23% वोटिंग हुई थी। 1977: वामपंथ (छा३३ ऋड्वल्ल३) के उदय के समय यह आंकड़ा 70% के पार चला गया। 2006: बुद्धदेव भट्टाचार्य के दौर में वोटिंग 81% तक पहुंची। 2011 (ऐतिहासिक बदलाव): जब ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी किले को ढहाया, तब रिकॉर्ड 84.33% मतदान हुआ था।
यह पैटर्न बताता है कि जब भी बंगाल में सत्ता परिवर्तन की सुगबुहाट होती है, वोटिंग का ग्राफ तेजी से ऊपर भागता है। 2011 का उदाहरण सबसे सटीक है, जहां बंपर वोटिंग ने वामपंथ की विदाई तय कर दी थी। क्या 2026 में भी इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है?

इसी वजह से जब भी बंगाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, राजनीतिक विश्लेषक 2011 के चुनाव की तुलना शुरू कर देते हैं। हालांकि हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। 2025 में भी विपक्ष दावा कर रहा है कि ज्यादा वोटिंग बदलाव का संकेत है, जबकि वोट उने अपने समर्थन का प्रमाण बता रही है।

उत्कृष्ट परिणाम आने पर विद्यालय

मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया। स्कूल प्रबंधन ने भी दोनों मेधावी छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। वहीं प्रतापगढ़ के सत्यम यादव ने 583 अंक पाकर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। उनके 97.17 प्रतिशत अंक बन रहे हैं। सत्यम यादव के पिता समर यादव ईंट

कुमारगंज में भाजपा के सुभेंदु को किया लहलुहान! आसनसोल में अग्निमित्रा की गाड़ी पर हमला

(जीएनएस)।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान हिंसा की आग और तेज हो गई है। नंदीग्राम के बाद अब कुमारगंज और आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारी तनाव देखा जा रहा है। कुमारगंज में भाजपा उम्मीदवार सुभेंदु सरकार ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं पर न केवल हमला करने, बल्कि उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करने का भी गंभीर आरोप लगाया है।

खुलासे किए हैं? सुभेंदु सरकार ने कहा कि, 'कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में 8-10 मतदान केंद्रों पर हमारे पोलिंग एजेंटों को जबरन हटा दिया गया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और सुनिश्चित किया कि उन्हें वापस अंदर जाने दिया जाए। जब मैं जमीनी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए बृहत् नंबर 24 पर गया, तो उन्होंने मेरी पूरी टीम और मुझ पर हमला कर दिया। वे स्पष्ट रूप से डराने-धमकाने

और डर का माहौल बनाने के इरादे में थे... केंद्रीय बल मतदान केंद्र पर ही मौजूद थे - वे परिसर के अंदर थे। लेकिन जब मैं मौके पर पहुंचा, तो मेरे साथ केवल मेरा अंगरक्षक था; हमारे साथ और कोई नहीं था।'
सुभेंदु सरकार ने कहा कि, 'ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, और तृणमूल कांग्रेस इस क्षेत्र की सभी चारों सीटें हार रही है। पूरी तरह से हताशा और डर के कारण, उन्होंने हम पर हमला किया।'
पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार में जमीनी स्थिति का निरीक्षण करने के दौरान उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया।

कोयंबटूर में 'रोबोट' कर रहा वोटर्स का स्वागत, हाथ जोड़कर बोला- वोट जरूर डालें
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 23 अप्रैल को हो रहे मतदान के बीच कोयंबटूर से तकनीक और लोकतंत्र के संगम की एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहां के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में बने मतदान केंद्र पर मतदाताओं का स्वागत कोई इंसान नहीं, बल्कि एक 'रोबोट' कर रहा है।
यह रोबोट न केवल लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहा है, बल्कि कतार में खड़े वोटर्स का मुंह भी मीठा करा रहा है।

इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन माहौल अब भी बेहद संवेदनशील बना हुआ है। आइए जानते हैं कुमारगंज में हमले के बाद सुभेंदु सरकार ने क्या बड़े

खुलासे किए हैं? सुभेंदु सरकार ने कहा कि, 'कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में 8-10 मतदान केंद्रों पर हमारे पोलिंग एजेंटों को जबरन हटा दिया गया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और सुनिश्चित किया कि उन्हें वापस अंदर जाने दिया जाए। जब मैं जमीनी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए बृहत् नंबर 24 पर गया, तो उन्होंने मेरी पूरी टीम और मुझ पर हमला कर दिया। वे स्पष्ट रूप से डराने-धमकाने

और डर का माहौल बनाने के इरादे में थे... केंद्रीय बल मतदान केंद्र पर ही मौजूद थे - वे परिसर के अंदर थे। लेकिन जब मैं मौके पर पहुंचा, तो मेरे साथ केवल मेरा अंगरक्षक था; हमारे साथ और कोई नहीं था।'
सुभेंदु सरकार ने कहा कि, 'ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, और तृणमूल कांग्रेस इस क्षेत्र की सभी चारों सीटें हार रही है। पूरी तरह से हताशा और डर के कारण, उन्होंने हम पर हमला किया।'
पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार में जमीनी स्थिति का निरीक्षण करने के दौरान उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया।

कोयंबटूर में 'रोबोट' कर रहा वोटर्स का स्वागत, हाथ जोड़कर बोला- वोट जरूर डालें
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 23 अप्रैल को हो रहे मतदान के बीच कोयंबटूर से तकनीक और लोकतंत्र के संगम की एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहां के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में बने मतदान केंद्र पर मतदाताओं का स्वागत कोई इंसान नहीं, बल्कि एक 'रोबोट' कर रहा है।
यह रोबोट न केवल लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहा है, बल्कि कतार में खड़े वोटर्स का मुंह भी मीठा करा रहा है।

इस्लामाबाद में लगा लॉकडाउन, शांति वार्ता के लिये स्कूल-ऑफिस-कारखाने सब बंद, जनता दे रही मुनीर को गालियां

(जीएनएस)।
अपनी राजनीतिक हसरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और आमी चीफ आसिम मुनीर किसी भी हद तक गिर सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 10 दिनों से वे अपनी कूटनीति को सफल दिखाने के लिए इस्लामाबाद की जनता का तेल निकाल रहे हैं। वहीं जनता भी उनकी हरकतों से त्रस्त होकर अब

गालियां देने लगी है।
दरअसल इस्लामाबाद में इस समय ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे फिर से कोरोना लॉकडाउन लग गया हो, लेकिन इसकी वजह कोई वायरस नहीं है। असल कारण है अमेरिका-ईरान शांति वार्ता, जिसके लिए राजधानी को हाई-सिक्विटीटी जोन में बदल दिया गया है। शहर की सड़कें खाली दिख रही हैं, स्कूल और दुकानें बंद हैं, और सरकारी

कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां तक की बोर्ड्स के एग्जाम टाल दिए गए और बच्चे अब इंतजार कर रहे हैं।
इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा है। कई मजदूरों का काम बंद हो गया है, जबकि कुछ लोग एक ही जगह फंसे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, और

इस वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा रद्द होने के बाद शांति वार्ता स्थगित हो गई थी। वजह बताई गई कि ईरान बातचीत में शामिल नहीं हो रहा। इसके बावजूद इस्लामाबाद में सुरक्षा पाबंदियां खत्म नहीं हुईं। रेड जोन में कड़ी सुरक्षा है, सड़कें बंद हैं, और स्कूल-कॉलेज अभी भी बंद पड़े हैं।

JioTV
CHENNAL NO. 2063

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba TV

Dish Plus

Jio Air Fiber

Jio tv+

Jio Fiber

Dailly Hunt

fire tv

Roku TV-US.UK

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

'हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की जिम्मेदारी, पैसे और जन्त का लालच', केजीएमयू के 12वीं पास 'डॉक्टर' पर बड़ा खुलासा

(जीएनएस)। लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में सनसनीखेज रैकेट का पदार्फाश हुआ है। खुद को डॉक्टर बताने वाला 12वीं पास जालसाज हस्साम अहमद, पैरामेडिकल छात्रों के साथ मिलकर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था। मेडिकल कैम्प और फर्जी कॉन्फ्रेंस के बहाने चल रहे इस खेल के तार अब धर्मांतरण से जुड़ रहे हैं।



लखनऊ पुलिस ने केजीएमयू प्रशासन की मदद से जालसाज हस्साम अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी खुद को 2017 बैच का केजीएमयू पासआउट डॉक्टर बताकर इंटर लड़कियों को झांसे में लेता था। इस नेटवर्क में मोहम्मद फैज और फईक अहमद मंसूरी जैसे सहयोगी शामिल थे, जो लड़कियों को

मुस्लिम बहुल इलाकों में मेडिकल कैम्प के नाम पर ले जाते थे। 19 अप्रैल को केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने एक कैम्प में छापेमारी कर इस फर्जी संस्था के अहमद मंसूरी है। इस नेटवर्क में शामिल मोहम्मद फैज को खास तौर पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लड़कियों को जोड़ने के बदले पैसें और 'जन्त' का हवाला दिया जाता था। आरोपी पहले भी संदिग्ध गतिविधियों के कारण पकड़ा जा चुका है और लड़कियों को बहलाने के आरोप में उसकी पिटाई भी हुई थी।

फर्जी डॉक्टर और एम्स के नाम पर धोखाधड़ी जालसाज ने छात्रों को दिल्ली एम्स में कार्डियो सर्जरी कॉन्फ्रेंस में ले जाने का झांसा दिया था। जब केजीएमयू प्रशासन ने एम्स से संपर्क किया, तो पता चला कि वहां ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। बच्चों को दिए गए पत्रों पर डॉ. केके सिंह समेत केजीएमयू के

कई जिम्मेदार अधिकारियों के फर्जी दस्तखत थे। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह के मुताबिक, यह गिरोह पहले लड़कियों को निशाना बनाता था और फिर उनका धर्मांतरण करवाता था।

पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर

डॉ. रमीज अहमद की गिरफ्तारी के बाद केजीएमयू ने एक विशेष कमेटी बनाई थी, जिसने इस रैकेट को उजागर किया। पुलिस अब हस्साम अहमद के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है और केस से जुड़े अन्य लोगों को पहचान की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस मामले में जल्द ही और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल, लखनऊ पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

भीषण गर्मी में बिजली संकट: लखनऊ के वीवीआईपी इलाके हजरतगंज में भी कटौती से हाहाकार

(जीएनएस)। राजधानी लखनऊ में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। हालात इतने खराब हैं कि शहर के वीवीआईपी इलाके हजरतगंज में भी बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमपराई हुई नजर आ रही है। लगातार हो रही कटौती से आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग तक सभी परेशान हैं।

गर्मी के साथ बढ़ा बिजली संकट लखनऊ में तापमान लगातार 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ऐसे में बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है, लेकिन आपूर्ति व्यवस्था उस मांग को पूरा करने में असफल साबित हो रही है। दिन हो या रात, कई इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

हजरतगंज में भी ठप व्यवस्था

शहर का दिल कहे जाने वाला हजरतगंज, जहां आमतौर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, वहां भी बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर दिया है। यह इलाका मुख्यमंत्री आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसके बावजूद यहां बिजली की अनियमित आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन में कई बार बिजली कट रही है, जिससे न केवल घरेलू काम प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि व्यापार पर भी असर पड़ रहा है।

व्यापारियों पर पड़ रहा असर हजरतगंज जैसे व्यस्त बाजार में बिजली कटौती का सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि बिना बिजली के एसी, पंखे और लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिससे ग्राहक दुकान में रुकना पसंद नहीं करते। इसके अलावा डिजिटल भुगतान और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं, जिससे कारोबार में गिरावट

जलकर राख हो गया बचपन, सपने अब भी जिंदा, मासूम बोली- मैं पढ़ूंगी

(जीएनएस)। लखनऊ के विकास नगर की झुग्गी बस्ती में आग ने कई परिवार तबाह कर दिए। अब वहां आग की लपटें भले ही न हों पर जला हुआ सामान अब भी उस भयावह रात की गवाही दे रहा है।

लखनऊ के विकासनगर की उस झुग्गी बस्ती में अब आग की लपटें नहीं हैं, लेकिन हर तरफ बिखरी राख और जले हुए सामान अब भी उस भयावह रात की गवाही दे रहे हैं। हवा में घुली जलेपन की गंध के बीच जब सुबह की धूप उतरती है, तो खंडहर बने आशियानों के बीच खेलते बच्चों की आंखों में डर, दर्द और उम्मीद तीनों एक साथ दिखाई देते हैं।

ये मेरी नई हिंदी की कांपी है... मैं पढ़ूंगी... उसकी आवाज में दर्द से वही हाथ राख के डेर में अपना भविष्य तलाशते नजर आते हैं।

सात वर्षीय राधा और नौ साल की

आ रही है। आम जनता की बढ़ी परेशानी बिजली कटौती का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। भीषण गर्मी में बिना बिजली के रहना मुश्किल हो गया है।



रात में नींद पूरी नहीं हो पा रहीपानी की सप्लाई प्रभावित हो रही हैछोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत हो रही है लोगों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में बिजली की कटौती असहनीय हो गई है।

बिजली विभाग पर उठे सवाल

लगातार हो रही कटौती को लेकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि हर साल गर्मी के मौसम में यही समस्या सामने आती है, लेकिन इसके समाधान के लिए कोई स्थायी कदम नहीं उठाया जाता। सूत्रों का मानना है कि बढ़ती आबादी और बिजली की मांग के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हो पा रहा है, जिससे यह समस्या लगातार बनी रहती है।

व्या है कारण

बिजली विभाग के अनुसार, बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की खपत में अचानक वृद्धि हुई है। इसके अलावा कुछ जगहों पर तकनीकी खराबी और ओवरलोडिंग की समस्या भी सामने आई है। हालांकि विभाग



अपनी काँपी दिखाते हुए कहती है कि ये मेरी नई हिंदी की काँपी है... मैं पढ़ूंगी... उसकी आवाज में दर्द से ज्यादा दृढ़ता झलकती है।

पास बैठी मां सुमित्रा देवी की आंखें भर आती हैं। वह कहती हैं, घर

का दावा है कि समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

अधिकारियों का कहना है कि बिजली आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही

उम्मीद नहीं है। बृहस्पतिवार के लिए यूपी के 22 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। बुधवार को बांदा में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं वहीं 43.7 डिग्री के साथ प्रयागराज प्रदेश में दूसरे नंबर पर रहा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 26 अप्रैल से एक नए विश्वीय के सक्रिय होने से प्रदेश भर में बादलों की सक्रियता बढ़ेगी और पश्चिमी यूपी, तराई आदि में बूंदबांदी से परे में गिरावट के संकेत हैं।

इन् जिलों में लू बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नोज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मेनपुरी व आस पास के क्षेत्र।

24 और 25 अप्रैल को लखनऊ में चलेगी लू

राजधानी में बुधवार को भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। शुल्का देने वाली धूप के साथ दिन में पछुआ हवाओं ने आग में घी का काम किया। अधिकतम तापमान में भी बहुत दर्ज की गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ में फिलहाल तीन दिन तक तापमान का बढ़ना जारी रहेगा। 24 व 25 अप्रैल को राजधानी में लू चलने की चेतावनी है। इसके बाद 26 अप्रैल से एक नया पश्चिमी प्रभाव से बादलों की सक्रियता बढ़ने और थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बुधवार को अधिकतम तापमान 0.9 डिग्री की बढ़त के साथ 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री की बढ़त के साथ 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और तपिश का प्रकोप लगातार जारी है। बुधवार को बुंदेलखंड इलाके के साथ ही कई अन्य जिले गर्म हवा और लू के थपेड़ों की चपेट में रहे। बांदा प्रदेश में सर्वाधिक गर्म रहा और देश में तीसरे नंबर पर रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 25 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी और लू से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा बढ़ेगा। फिलहाल अगले दो दिनों तक इस प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की

बोली- मैं पढ़ूंगी

बस्ती में कई बच्चे हैं, जो अब खेलते नहीं, बल्कि चुपचाप अपने माता-पिता को देखते रहते हैं। माता-पिता बांस और तिरपाल के सहारे फिर से छत खड़ी करने में जुटे हैं, जबकि कुछ कुछ बच्चे भी उनके साथ हाथ बंटा रहे हैं। हालात ने उन्हें वक्त से पहले बड़ा बना दिया है।

अग्निकांड की जांच होगी, 13 मई तक मांगी रिपोर्ट वहीं, हाईकोर्ट ने विकास नगर में 15 अप्रैल को हुए अग्निकांड मामले में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण होने के मुद्दे पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जांच करने का आदेश दिया है। उन्हें अपना रुख भी बताना होगा। कोर्ट ने प्रदेश के राहत आयुक्त को भी मामले में जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही पक्षकार अफसरों को घटना का विवरण, कारण, राहत के उपायों के व्योरे के साथ 13 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

लखनऊ से पश्चिम बंगाल लौट रहे सारे बंगाली, चुनावी समंदर में 'मछली' का बड़ा खेल

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोग इन दिनों सामान बांधकर पश्चिम बंगाल की ओर रवाना हो रहे हैं। वजह है- 23 और 29 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालना। लेकिन इस बार उनकी यात्रा सिर्फ मताधिकार का नहीं, बल्कि एक बड़े सांस्कृतिक-चुनावी मुद्दे का हिस्सा बन गई है 'मछली बनाम शाकाहार'।

लखनऊ के मशहूर भोजनालय में कबाब बनाने वाले शफीकुल और हरि सभा मंदिर के पुजारी तारक नाथ भट्टाचार्य दोनों बंगाल पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच दो चीजें कॉमन हैं, बंगाल उनका गृह राज्य है और दोनों 'माछ-भात' के बिना अपना भोजन अधूरा मानते हैं। कैसे बंगाल के इस हाई-वोल्टेज चुनाव में मछली अब सिर्फ थाली का व्यंजन नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार बन गई है।

पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से मांसाहारी समाज है। यहां मछली-चावल रोजमर्रा का भोजन है। लेकिन चुनावी मौसम में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। छट्ट का आरोप है कि अगर इखट सत्ता में आई तो मछली, मांस और अंडे पर पाबंदी लगा देगी। इस आरोप की धार कुंद करने के लिए इखट ने अपने नेताओं को सार्वजनिक रूप से मछली और मांस खाते दिखाया। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 अप्रैल को कहा कि

अगर प्रधानमंत्री मछली खाना चाहते हैं, तो मैं खुद उनके लिए पाकअंगी। लखनऊ के पुजारी तारक नाथ भट्टाचार्य (45 वर्ष) ने ढक्कन से कहा कि माछ भात-ए बंगाली। बंगाली घरों

शफीकुल के अनुसार, खाने की आदतें भावनात्मक मुद्दा बन गई हैं। जब मुकाबला कड़ा होता है, तो रिविंग वोटर इन्हीं मुद्दों से प्रभावित होते हैं। लखनऊ के रबींद्रपल्ली में रहने

मंछली-चावल मुख्य भोजन है। वे पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा विधानसभा क्षेत्र में वोट डालने गए हैं, जहां 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। भट्टाचार्य ने बताया कि 18 साल की उम्र से हर चुनाव में मैं बंगाल जाता हूँ। इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है। लेकिन 'शाकाहारी बनाम मांसाहारी' वाली बहस मुझे हैरान कर रही है।

लखनऊ से बंगाल तक: रसोइए और पुजारी क्यों लौट रहे हैं? लखनऊ के मशहूर भोजनालय में कबाब शेफ शफीकुल (मालदा जिले के चंचल विधानसभा क्षेत्र के मतदाता) ने बताया कि लखनऊ और वड के कई रेस्टोरेंट में बंगाल के रसोइए, हेल्पर और वेंटर काम करते हैं। इस बार सभी पार्टियां वोटरों को लाने के लिए हर कोशिश कर रही हैं।

व्यो बनी मछली चुनावी मुद्दा? 2024 लोकसभा चुनाव में BJP को 'बाहरी' पार्टी बताया गया था। इस बार छट्ट ने इसे और आगे बढ़ाया, BJP आएगी तो मछली-मांस बंद। BJP ने जवाब में नेताओं को

मछली खाते दिखाकर कांटेर किया। शफीकुल ने कहा कि पहले कभी खाने की आदत चुनाव का मुद्दा नहीं बनी थी। इस बार जरूर कोई जवाह है। उन्होंने वोटर लिस्ट के SJR का भी जिक्र किया, जिसे लेकर बंगाल में पहले विवाद हुआ था।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सीटों वाले चुनाव दो चरणों (23 और 29 अप्रैल) में होंगे। नतीजे 4 मई को आएंगे। पहले चरण में करीब 3.60 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। इस बार के मुद्दे सिर्फ मछली तक सीमित नहीं, सीमा घुसपैट, समान नागरिक संहिता (UCC) और विवाहित वोटर लिस्ट भी गरमा रहे हैं। लेकिन 'मछली' ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं क्योंकि यह बंगाली पहचान से सीधा जुड़ा है।

खाने की थाली से निकला राजनीतिक स्वाद लखनऊ से बंगाल लौट रहे बंगाली रसोइए, पुजारी और मजदूर इस बार सिर्फ वोट देने नहीं जा रहे, वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। 'माछ-भात' अब सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि बंगाल की अस्मिता का प्रतीक बन गया है। छट्ट इसे इखट के खिलाफ हथियार बना रही है, तो इखट इसे 'संस्कृति बचाओ' का मुद्दा बता रही है। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान शुरू होगा। देखा ना होगा कि मछली की इस थाली वाली बहस रिविंग वोटर को किस तरफ ले जाती है।

रा. इण्टर कॉलेज में हुआ जनपद स्तरीय योग ओलिंपियाड का आयोजन

सीतापुर। (जीएनएस)। आज दिनांक 23.04.2026 को राजकीय इण्टर कॉलेज में जनपद स्तरीय योग ओलिंपियाड का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन राजकीय इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य अशोक कुमार ने किया।

इस प्रतियोगिता में जनपद के नौ ब्लॉकों की टीमों ने बालक वर्ग और बालिका वर्ग में प्रतिभाग किया। बालक वर्ग में शिवांशु दीक्षित, सेवाश्रम इण्टर कॉलेज, काजीकमालपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में सोनाली ने प्रथम और रेशमा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। दोनों ही बालिकाएं उजागर



लाल इण्टर कॉलेज की छात्राएं हैं। जनपद स्तर पर विजयी खिलाड़ी

मंडलीय योग प्रतियोगिता जिसका आयोजन दिनांक 24.04.2026 को राजकीय इण्टर कॉलेज, निशातगंज, जनपद लखनऊ में किया जाएगा में प्रतिभाग करेंगे।

प्रतियोगिता का संचालन जिला क्रीड़ा सचिव अवधेश नन्दन पाण्डेय ने किया। निष्कर्षों के रूप में पवन कुमार, विवेक कुमार शुक्ल, डॉ. निखिल कुमार रस्तोगी, प्रभात नंदन मिश्र, लक्ष्मी और रौनक आदि लोग उपस्थित रहे।

इस अवसर पर राजकीय इण्टर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य डॉ. नरेंद्र सिंह, फूलचंद्र आदि लोग मौजूद रहे।

स्वच्छता की नई इबारत: महोबा के विद्यालय में छात्राओं के लिए नवनिर्मित पिंक शौचालय का लोकार्पण

(जीएनएस)। महोबा/श्रीनगर - भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत अभियान' को धरातल पर उतारते हुए जनपद के विकास खंड कबरई में महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता की एक नई मिसाल पेश की गई है। ग्राम बिलरही के गुप्ता खोदा स्थित कम्पोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के लिए विशेष रूप से निर्मित पृथक शौचालय का लोकार्पण किया गया।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, श्री रोशन लाल, आयुक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, कानपुर के सराहनीय सहयोग से सार्वजनिक हित में इस आधुनिक सुविधा का निर्माण केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) मंडल-कानपुर देहात द्वारा कराया गया

है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य



अतिथि रामशंकर (अधीक्षक, CGST रंज-महोबा) द्वारा माँ शारदे के पूजन

और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर ग्रामीण परिवेश के बच्चों

जिसने उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए अधीक्षक विवेक मिश्र ने बेहद सरल और रोचक शैली में छात्रों। अभिभावकों से संवाद करते हुए उन्हें CGST विभाग की कार्यशैली एवं महत्व बताते हुए, देश के विकास में विभाग का योगदान और सामाजिक दायित्वों के निर्वाहन के विषय में बहुत ही सरल शब्दों समझाया और उन्हें मन लगाकर पढ़ने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

मुख्य अतिथि राम शंकर ने अपने संबोधन में विभाग की कार्ययोजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग केवल कर संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों के तहत सुदूर ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्राओं के लिए सुरक्षित शौचालय की उपलब्धता से उनके नामांकन और शिक्षा के स्तर में सकारात्मक सुधार आएगा।

इस गौरवशाली पल के साक्षी मनीष मिश्रा (हवलदार), प्रधानाध्यपक शिवनंदन कुशवाहा, शिक्षक भारती तिवारी, अनिल कुमार निरंजन, रवेन्द्र गौतम के साथ-साथ किसान यूनियन के बृजेंद्र कुमार तिवारी, समाजसेवी शोभित मिश्रा, राजेश गोस्वामी और राजा सेन रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन शिक्षक अनिल रावत ने किया। लोकार्पण के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक उपस्थित रहे, जिन्होंने विभाग की इस पहल की मुक्त कंठ से सराहना की।

सीतापुर में हाईटेंशन तार गिरने लगभग दस बीघा पेड़ी गन्ने की फसल जलकर खाक

(जीएनएस)। सीतापुर जिले के खैराबाद ब्लॉक स्थित खैरमपुर भिमरी गांव में हाईटेंशन बिजली का तार गिरने से किसान राम सिंह यादव की लगभग दस बीघा गन्ने की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। इस घटना में खेत में बिछी 500 फुट पानी की पाइप भी जल गई।

यह घटना मोहर सिंह यादव तथा श्रीराम यादव (पूर्व प्रधान)के खेत से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के तार के अत्यधिक नीचे लटकने के कारण हुई। तार इतना नीचे था कि उसे हाथ से छुआ जा सकता था। तार गिरने से निकली चिंगारी ने तुरंत गन्ने की फसल को अपनी चपेट में ले लिया।

आग लगने की सूचना पर ग्रामीण



सोनु, मोनु, पंकज, श्रीराम प्रधान और विपिन सहित कई अन्य लोग मौके पर

सोनु, मोनु, पंकज, श्रीराम प्रधान और विपिन सहित कई अन्य लोग मौके पर

सकती थी, जिससे किसानों को और अधिक नुकसान होता। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारी ओमप्रकाश से कई बार इन लटके हुए तारों की शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि इन लटके तारों से कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है।

किसान राम सिंह यादव ने घटना की सूचना लेखपाल प्रीति पाल को दे दी है, जो इसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगी। किसान ने प्रशासन से अपनी जली हुई फसल और पाइप के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। जिससे किसान गन्ने की बुवाई पुनः कर सके।

सम्पादकीय

मौजूदा दौर में बड़ा सवाल आखिर होर्मुज पर किसका राज है और आगे किसका राज चलेगा ?

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले करीब 50 दिनों से जारी तनाव के कारण शांति वार्ता खटाई में पड़ती दिख रही है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में सक्रिय बना हुआ है। होर्मुज की ताजा तनावनी को देखते हुए पाकिस्तानी मध्यस्थता टीम वापस इस्लामाबाद लौट चुकी है। पाकिस्तान में पहले दौर की शांति वार्ता के बाद अमेरिका ने होर्मुज का ब्लॉकड लागू कर दिया है। वहीं ईरान ने इसे अपनी संप्राभुता पर हमला बताया है। समुद्र में ईरानी जहाजों तक को भी रोका जा रहा है और तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। दुनिया की नजर अब इस पर है कि इस टकराव का अगला कदम क्या होगा ? सवाल यह भी है कि आखिर होर्मुज पर किसका राज है और आगे किसका राज चलेगा ? ईरान और अमेरिका के बीच लगभग 40 दिनों तक भीषण युद्ध चला। इसके बाद बड़ी मुश्किल से सीजफायर का ऐलान किया गया और इस्लामाबाद में शांति वार्ता बुलाई गई। लेकिन यह बातचीत बेतनीजा रही। बातचीत पेल होने का सबसे बड़ा कारण होर्मुज रहा। होर्मुज पर किसका दबदबा रहेगा इसका पैसला नहीं हो सका। फिलहाल तो शांति वार्ता के बाद ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज पर कब्जे को लेकर संर्सेस की आग धधक रही है। अमेरिका और ईरान आमने-सामने खड़े हैं। दुनिया में तेल के इस अहम रास्ते पर किसका कब्जा है, किसके हाथ में है ? सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। दोनों खेमे अपने-अपने दावों पर अड़े हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती ने माहौल और गरमा दिया है। कई देशों की अर्थव्यवस्था इसी रास्ते पर टिकी हुई है। बता दें कि दुनिया की आधी से ज्यादा तेल सप्लाई इसी रास्ते पर निर्भर है। एक छोटी सी गलती भी ग्लोबल इकॉनमी को हिला सकती है। अमेरिका का ब्लॉकड कितना कारगर साबित हो रहा है ? या ईरान की धमकी में दम है ? संर्सेस हर घंटे बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को ईरानी जहाज को अमेरिका ने होर्मुज से वापस लौटाया है इसके बाद तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। सीजफायर के बावजूद अमेरिका की इस हरकत से ईरान का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ईरान ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की सख्त चेतावनी दी है। डर इसका है कि युद्ध विराम जो 23 अप्रैल को खत्म हो रहा है वह आगे बढ़ेगा या नहीं ? होर्मुज के बंद होने से अब यह टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं रहा। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। तेल बाजार में उथल-पुथल है, शिपिंग कंपनियां सतर्क हो गई हैं। हर देश चाहता है कि यह अहम रास्ता खुला रहे। लेकिन जमीन और समुद्र पर चल रही रणनीतिक चालें इस रास्ते को सबसे बड़ा फ्लैश प्वाइंट बना रहा है। ट्रंप ने रायटर्स को दिए एक और बयान में दावा किया कि ब्लॉकड पूरी तरह लागू है और ईरान अब सामान्य व्यापार नहीं कर पा रहा है। सेटकोंम के अनुसार अब तक 10 जहाजों को वापस भेजा जा चुका है। इस बीच खबर यह भी आई है कि पाकिस्तानी सेना प्रामुख आसिम मुनीर ने ट्रंप को सुझाव दिया है कि अगर शांति वार्ता आगे बढ़ानी है तो होर्मुज से ब्लॉकड समाप्त करना होगा। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कहा— मैं विचार करूंगा।

'लखनऊ के इकाना की पिच पर्थ के वाका जैसी', एलएसजी के हेड कोच जस्टिन लैंगर का बयान वायरल

(जीएनएस)। लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने इकाना की पिच को लेकर हैरान करने वाला बयान दिया है। यहां जानें उन्होंने क्या कुछ कहा। लखनऊ के इकाना की पिच हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। पिछले सीजन कई मैचों में यहां रन बनने लगे थे, लेकिन एक बार फिर अब इस पिच पर सवाल उठने लगे हैं। अब यहां की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने लखनऊ के इकाना की पिच को पर्थ के वाका जैसी बताया है। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने अपने घरेलू मैदान पर अब तक खेले गए तीनों मैच हारे हैं। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के खिलाफ उसे यहां हार का सामना करना पड़ा। जबकि बुधवार को राजस्थान रॉयल्स ने उसे 40 रन से हराया। पिछले सीजन में भी एलएसजी ने आपको गति और उछाल दोनों देखने को मिलते हैं। हम अभी तक इससे हमने कई ऐसी पिचें देखी हैं जहां गेंद अधिक उछाल नहीं लेती है, लेकिन यह पिच वाका की पिच की तरह है। यहां गेंद को अच्छी गति और उछाल मिलती है। यहां आपको वाकई दिलचस्प क्रिकेट देखने को मिल रहा है। हमारी बल्लेबाजी लाइनअप को देखते हुए सीजन की शुरुआत में किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि हमारे बल्लेबाज लय हासिल नहीं कर पाएंगे। हमने इसकी कल्पना भी नहीं की थी और इसलिए हम इस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं।



यहां खेले गए आठ मैचों में से छह मैच हारे थे। इस तरह से उन्होंने इस मैदान पर खेले गए 22 मैचों में से केवल नौ में जीत हासिल की है। लैंगर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यहां की पिच भारत के दूसरे स्थानों की पिच से बहुत अलग है। यह क्रिकेट के लिए शानदार पिच है। यहां

सामंजस्य नहीं बिटा पाए हैं। हम इस पिच पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बल्लेबाज इससे मिलने वाले अतिरिक्त गति और उछाल से तालमेल नहीं बिटा पा रहे हैं। हमारे बल्लेबाज कई बार शॉर्ट पिच गेंदों पर आउट हुए।" लैंगर ने आगे कहा, "भारत में

इकाना में लखनऊ की लगातार सातवीं हार, नाम किया यह शर्मनाक रिकॉर्ड, इस टीम ने घर पर हारे हैं सबसे ज्यादा मैच

(जीएनएस)। लखनऊ सुपर जायंट्स का अपने घरेलू मैदान पर प्रदर्शन इस सीजन बेहद निराशाजनक रहा है। राजस्थान रॉयल्स के हाथों मिली यह हार उनके घरेलू मैदान पर इस सीजन की लगातार तीसरी हार है। इसके साथ ही एकाना स्टेडियम में लखनऊ की यह लगातार सातवीं हार है। IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 32वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रनों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ की एकाना में लगातार 7वीं हार लखनऊ सुपर जायंट्स का अपने घरेलू मैदान पर प्रदर्शन इस सीजन बेहद निराशाजनक रहा है। राजस्थान रॉयल्स के हाथों मिली यह हार उनके घरेलू मैदान पर इस सीजन की लगातार तीसरी हार है। इसके साथ ही एकाना स्टेडियम में लखनऊ की यह लगातार सातवीं हार है। इस हार ने लखनऊ सुपर



जायंट्स को आईपीएल के अनचाहे रिकॉर्ड में दो पुरानी टीमों के साथ बराबरी कर दी है। डेक्कन चार्जर्स ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में लगातार सात घरेलू मैच गंवाए थे। इसी तरह पुणे वॉरियर्स इंडिया ने भी अपने पुणे के घरेलू मैदान पर लगातार सात हार झेली थीं। अब लखनऊ सुपर जायंट्स भी इस अनचाहे क्लब में शामिल हो गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने हार हैं सबसे ज्यादा मैच हालांकि, घरेलू मैदान पर सबसे लंबे हार के सिलसिले का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स (DC) के नाम है। टीम ने 2013 से 2015 के बीच अरुण

'टीएमसी के भ्रष्टाचार-गुंडागर्दी का सूरज डूब गया'

वोटिंग खत्म होने के बाद अमित शाह की पोस्ट से मची हलचल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को संपन्न हो गया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 91.35% फीसदी बंपर वोटिंग हुई। गुरुवार को संपन्न हुआ मतदान भारी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी के बावजूद हिंसक और विवादों से भरा रहा। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आगजनी, मारपीट और तोड़फोड़ के गंभीर मामले सामने आए, जिससे चुनावी माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, सिलीगुड़ी और मालदा जैसे क्षेत्रों में जमकर बवाल देखने को मिला। हिंसक घटनाओं के बीच बंगाल में पहले चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट

लिखी, जिसने सबका ध्यान खींचा है। अमित शाह ने एक सूर्यास्त की फोटो शेयर कर अंग्रेजी और बंगला में लिखा 'TMC के भ्रष्टाचार-गुंडागर्दी का सूरज डूब गया', 'सरकार बनते ही "दीदी के गुंडों" को बख्शा नहीं जाएगा' इसके साथ ही अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में अपने चुनावी अभियान के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) के समर्थकों को कड़ी चेतावनी दी है। पूर्वी बर्दवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 2 मई को भाजपा की सरकार बनते ही "दीदी के गुंडों" को बख्शा नहीं जाएगा। यह चेतावनी राज्य में बढ़ती राजनीतिक हिंसा के मद्देनजर दी गई थी, और रैली तीसरे चरण के मतदान से पहले आयोजित की गई थी।

"टीएमसी के गुंडों ने 130 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है" गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने 130 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ऐलान किया, "2 मई को भाजपा की सरकार बनने के बाद, सभी गुंडों को पाताल से भी दूँदकर कानून के तहत जेल भेजा जाएगा।" शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे तीसरे चरण के मतदान के दौरान टीएमसी समर्थकों द्वारा मतदान केंद्रों पर बाधा डालने पर भयभीत न हों।



कबीर के काफिले पर लाठी और इंटों से हमला हुआ। टीएमसी और एजेयूपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद कबीर ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कूचबिहार के तूफानगंज में

मतदान के दौरान भारी भीड़ से तनाव बढ़ गया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित किया। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में भाजपा उम्मीदवार सुवेदु सरकार पर हमला हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की। मालदा के मोथावाड़ी में ईवीएम खराबी के बाद मतदाता भड़क गए। गुस्साए लोगों ने चुनाव अधिकारी को घेरकर बंधक बना लिया और हाथापाई की। हरिश्चंद्रपुर में तृणमूल कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए।

मंत्री ताजमुल हुसैन के गांव में पार्टी कैंप कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। टीएमसी नेता स्वपन अली ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मंत्री और उनके समर्थक कांग्रेस के साथ मिलकर हमला करवा रहे थे। सिलीगुड़ी के एक बूथ पर टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। मौके पर मौजूद शंकर घोष के बीच उअदम्य ने हलात संभाले। आसनसोल उत्तर से मलय घटक ने बाहरी लोगों के आने का आरोप लगाया। उन्होंने गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार से लोगों को लाने के सबूत देने की बात कही।

'बंगाल में एसआईआर के विरोध में बंपर वोटिंग, ये टीएमसी की जीत का संकेत', बोर्ली सीएम ममता, शाह पर लगाया गंभीर आरोप

(जीएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण ने सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक तरफ जहां रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच चुनौती जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटिंग के बाद कहा है कि बंगाल की जनता ने स्मरक के विरोध में बंपर वोटिंग की है। सीएम ममता बनर्जी ने पहले चरण में हुई भारी वोटिंग को अपनी पार्टी के पक्ष में बताया और इसे जनता के गुस्से

और विरोध का संकेत कहा है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने एक्स पोस्ट में कहा है कि, 'TMC के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज डूब चुका है।' बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले बनर्जी और पीएम मोदी के बीच फेज में 89.93% मतदान हुआ है। (चुनाव आयोग के आंकड़े शाम 5 बजे तक हैं) ममता का शाह पर तीखा हमला: 'कोलकाता में बैठकर अफसरों को धमका रहे हैं' बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर

गंभीर आरोप लगाए हैं। दीदी का कहना है कि अमित शाह मतदान के दिन कोलकाता में डेरा डाले हुए हैं और वहां बैठकर अधिकारियों को डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं।



ममता ने सवाल उठाया कि जब चुनाव चल रहे हैं, तो केंद्रीय एजेंसियों का इस तरह इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है ? ममता बनर्जी के मुताबिक, बीजेपी के पास बूथों पर खड़ा करने के लिए एजेंट तक नहीं हैं, इसीलिए वे सरकारी मशीनरी और एजेंसियों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में जो 89.93% की बंपर वोटिंग हुई है, वह दरअसल केंद्र की नीतियों और SJR के विरोध में जनता का गुस्सा

है। दीदी ने तंज कसते हुए पूछा कि अगर चुनाव निष्पक्ष हैं, तो बीजेपी अभी से जीत के दावे कैसे कर रही है ? क्या उन्होंने ईवीएम (EVM) में कुछ फिक्सिंग कर रखी है ?

पीएम मोदी का पलटवार: 'झालमुड़ी मैंने खाई, पर मिर्ची TMC को लगी' दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कृष्णानगर की रैली में ममता बनर्जी पर अपने अंदाज में पलटवार किया। पीएम ने अपने हालिया 'झालमुड़ी' ब्रेक का जिक्र करते हुए कहा, "झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन उसकी झाल (मिर्ची) टीएमसी को लगी है।" पीएम ने दावा किया कि बंगाल की जनता टीएमसी के 'महा

जंगलराज' और घुसपैटियों को संरक्षण देने वाली नीति से तंग आ चुकी है। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे, तो बंगाल में जीत का जश्न होगा। उन्होंने वादा किया कि जीत के बाद न केवल मिठाइयां बंटेंगी, बल्कि झालमुड़ी भी खिलाई जाएगी। पीएम ने मतुआ और नामशुद्र समुदाय को गारंटी दी कि बीजेपी की सरकार बनते ही उअअ के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। CAA और शरणार्थी समुदाय पर बड़ा संदेश पीएम मोदी ने चुनावी मंच से मतुआ और नामशुद्र समुदाय को संदेश देते हुए कहा कि अगर BJP सरकार बनती है, तो नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत नागरिकता प्रक्रिया तेज की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शरण लेने वाले परिवारों को अधिकार और सुरक्षा दी जाएगी। यह बयान बंगाल की राजनीति में खास महत्व रखता है क्योंकि राज्य में शरणार्थी समुदाय चुनावी रूप से प्रभावशाली माना जाता है।

चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण: क्या कहते हैं पहले फेज के नंबर ? पहले चरण में 294 सीटों में से 152 सीटों पर मतदान हुआ है। लगभग 90 प्रतिशत के करीब हुई इस वोटिंग को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं। ममता बनर्जी इसे बीजेपी के खिलाफ जनादेश मान रही हैं, तो वहीं मोदी इसे टीएमसी के कुशासन के अंत की शुरुआत बता रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इतनी भारी संख्या में मतदाताओं का निकलना अक्सर बड़े बदलाव का संकेत होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ज्यादा मतदान हमेशा किसी एक दल के पक्ष में नहीं जाता। कई बार यह सत्ता विरोधी माहौल का संकेत होता है, तो कई बार मजबूत संगठन भी ज्यादा वोटिंग निकालने में सफल रहता है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी पद का मोह नहीं है, उनका एकमात्र लक्ष्य केंद्र से बीजेपी की विदाई है। फिलहाल, दीदी भवानीपुर में रोड शो कर दूसरे फेज की तैयारी में जुट गई हैं।

प्रवेश वाही - जो होंगे दिल्ली के मेयर! डिप्टी मेयर के लिए मोनिका पंत का नाम

(जीएनएस)। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म हो चुका है। लंबे इंतजार और कयासों के बाद, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। महापौर पद के लिए पार्टी ने वरिष्ठ पार्षद प्रवेश वाही को उम्मीदवार बनाया है, जो रोहिणी ई (वार्ड संख्या 53) से पार्षद हैं। वहीं, उप-महापौर पद के लिए आनन्द विहार (वार्ड संख्या 206) से पार्षद मोनिका पंत के नाम की घोषणा की गई है। इसके बाद दिल्ली की सियासत में चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब प्रवेश वाही का मेयर बनना लगभग तय माना जाय। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी (अअड) की रणनीति, बीजेपी की संख्या और नगर निगम की मौजूदा स्थिति इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रही है। बीजेपी ने स्थायी समिति के पदों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की है। जय भगवान यादव (बेगमपुर, वार्ड 27) को सदस्य स्थायी समिति एवं नेता सदन के लिए और मनीष चड्ढा (पहाड़गंज, वार्ड 82) को सदस्य स्थायी समिति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवेश वाही दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र से आने वाले प्रवेश वाही लंबे समय से स्थानीय राजनीति में सक्रिय माने जाते हैं। बीजेपी ने उन्हें 53-रोहिणी ई वार्ड से पार्षद के रूप में आगे बढ़ाया है। बताया जाता है कि वह तीसरी बार पार्षद बने हैं। इससे पहले वह 2007 से 2012 के बीच भी पार्षद रह चुके हैं और फिर 2022 में दोबारा चुनाव जीतकर निगम राजनीति में लौटे। प्रवेश वाही की राजनीतिक यात्रा स्थानीय स्तर से शुरू हुई। उनकी पहचान संगठनात्मक कार्यकर्ता और

क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में रही है। परिवार की पृष्ठभूमि भी संघर्ष से जुड़ी रही है। बताया जाता है कि उनके पिता पाकिस्तान से भारत



आए थे। पहले परिवार कश्मीर में रहा और बाद में दिल्ली में बस गया। यही वजह है कि वाही की कहानी को राजनीतिक गलियारों में एक सामाजिक संघर्ष और जमीनी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। क्यों चुना प्रवेश वाही ? दिल्ली में मेयर चुनाव केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होता। यह नगर निगम के प्रशासन, विकास योजनाओं और राजनीतिक संदेश से भी जुड़ा होता है। बीजेपी ने प्रवेश वाही को उम्मीदवार बनाकर एक ऐसा चेहरा सामने रखा है जो लंबे समय से निगम राजनीति के समझता है। पार्टी के भीतर माना जा रहा है कि वाही का अनुभव और संगठन में पकड़ उन्हें मजबूत उम्मीदवार बनाती है। साथ ही, रोहिणी जैसे इलाके से आने वाले नेता को आगे लाना उत्तर-पश्चिम दिल्ली के वोटर आधार को भी संदेश देने की रणनीति माना जा रहा है। डिप्टी मेयर के लिए मोनिका पंत पर भरोसा महापौर के साथ बीजेपी ने उप-महापौर पद के लिए मोनिका पंत के नाम की भी घोषणा की है। मोनिका

पंत 206-आनंद विहार वार्ड से पार्षद हैं। पार्टी ने उन्हें डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाकर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश

मौका दे रहे हैं ताकि जनता के सामने उनकी "नाकामी" पूरी तरह उजागर हो सके।

भारद्वाज ने दावा किया कि पिछले एक साल में जब भाजपा के पास सभी संसाधन और जिम्मेदारियां थीं, तब भी वे दिल्ली में कोई बड़ा बदलाव लाने में असफल रहे। उन्होंने केंद्र सरकार, एलजी और मेयर जैसे पदों पर भाजपा के नियंत्रण का जिक्र करते हुए कहा कि समस्याएं आज भी वैसी ही बनी हुई हैं। यह 'आप' की एक सोची-समझती राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है, जहां वे भाजपा को काम करने का "बहाना" न देकर सीधे जनता की अदालत में खड़ा करना चाहते हैं। नामांकन का आखिरी दिन और चुनाव की तारीख नगर निगम में महापौर, उप-महापौर और स्थायी समिति सदस्य के लिए नामांकन की अंतिम तारीख तय की गई है। नामांकन का आखिरी दिन बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी से यह साफ होगा कि मुकाबला सीधा होगा या निर्विरोध स्थिति बन सकती है। चुनाव की प्रक्रिया अप्रैल के अंतिम सप्ताह में पूरी होगी। निगम सचिव कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार चुनाव 26 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे। बैठक अरुणा आसफ अली सभागार में होगी, जहां मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मतदान होगा। दिल्ली मेयर चुनाव इतना अहम क्यों है ? दिल्ली का मेयर पद केवल एक सम्मानजनक राजनीतिक कुर्सी नहीं है। नगर निगम का प्रशासन, सफाई व्यवस्था, पार्क, सड़कों की मरम्मत, स्थानीय विकास और बजट जैसे कई फैसले इसी व्यवस्था से जुड़े होते हैं। राधानी में मेयर की भूमिका हर साल बदलती रहती है। दिल्ली में मेयर का कार्यकाल एक साल का होता है।

